subjudice. So, can we discuss it in the House? That is my point. ..*(Interruptions)*..

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): Now Mr. Upendra, you were a Minister. You know it pretty well.

SHRI P. UPENDRA: We never did such things.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): I cannot compel the Ministers to respond unless and until they come forward. Now, that matter is over. Yes, Shri Sibtey Razi.

Re. Supply of F-16 aircraft to Pakistan by U.S.A.

SYED SIBTEY RAZI (Uttar Pradesh): Sir, with your permission I rise to appreciate and welcome the recent statement of the representative of the US State Department Mr. David Johnson. He has stated that the US Government had decided not to supply F-16 aircraft to Pakistan. We welcome and appreciate the stand taken by the US Government, because whenever such sophisticated aircraft or weapons and armaments had been supplied to Pakistan, they had been used against us. My submission through you, Sir, is that the US should completely scrap this contract, as it appears from the statement that the offer is still lying on the table for negotiations. It was suspended for some time, but we expect that, keeping in view the situation in this region, the supply of F-16 aircraft to Pakistan will create an imbalance of power in this region. We also appreciate the stand taken by the US Congress, that generally the US Congress does not support such stand taken by the State Department. My submission is that this sort of supply should not be effected to Pakistan, as Pakistan has made some atom bombs and these F-16 aircraft have a system for the delivery of atomic bombs. In this situation, the US Government's decision not to supply F-16 aircraft to Pakistan is a good one. But I feel that the contract for this supply should be scrapped once for all.

The recent visit of our hon. Prime Minister, Shri P.V. Narasimha Rao, to the United States, his address to the US Congress as well as his negotiations and discussions with the US largest democracies of the world have come closer, and we hope that peace and tranguillity in this region will be maintained and nothing will be done for the supply of such armaments to Pakistan. In 1990 also, the US Government cancelled all its economic and military aid to Pakistan. Pakistan is continuously trying to destabilise our country in this region. It has started a proxy war against us. The destabilisation process is going on in J&K. Each and every step of Pakistan is heading towards destabilisation of this country and disturbance of peace and tranquillity in this region. I hope the U.S. will try to appreciate this. Whenever a U.S. representative came to our country or whenever our representative went to their country, we tried to get them know our position in this regard. With these words, I thank you very much.

Re. Demand for supply of relevant documents to jain commission

श्री सुरेश पचौरी (मध्य प्रदेश): माननीय उप-सभाध्यक्ष जी, इस माननीय सदन में 13 मई 1994 को विशेष उल्लेख के माध्यम से मैंने सदन का ध्यान आकर्षित किया था कि श्री राजीव गांधी की निर्मम हत्या की जांच का पता करने के लिए जो जैन कमीशन का गठन किया गया है, उसे पर्याप्त दस्तावेज नहीं दिये जा रहे हैं। इस संबंध में मैंने पूरा ब्यौरा भी प्रस्तुत किया था कि कौन-कौन से दस्तावेज चाहे गये हैं जो अभी तक जैन कमीशन को उपलब्ध नहीं कराए गये हैं। 14 मई 1994 को मैंने इस संबंध में माननीय गृह मंत्री जी को भी पत्र लिखा जिसका उत्तर 21 जून 1994 को मुझे प्राप्त हुआ जिसमें उन्होंने यह उल्लेख किया है कि

> "The question of providing the relevant documents, material etc. to the Commission is already receiving the attention of the Government, and we will be filing our reply in the matter. Government has already provided certain documents material to the Commission.

माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं बड़े अफसोस के साथ आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि अभी हाल में 9 अगस्त को जो जैन कमीशन से सुनवाई हुई, उस तारीख तक जो दस्तावेज जैन कमीशन

सरकार से चाहे थे, वह उसे उपलब्ध नहीं हो पाए और जस्टिस एम.सी.जैन ने संडे को दिये गये साक्षात्कार में बड़े दुख के साथ इस बात को व्यक्त किया है कि सरकार की तरफ से, चाहे वह तमिलनाडु की सरकार हो, चाहे केन्द्रीय सरकार हो, उनकी तरफ से कमीशन को वांछित सहयोग प्राप्त नहीं हो रहा है। माननीय महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि यद्यपि हमारे प्रधान मंत्री श्री नरसिंह राव जी ने इसको बहुत गंभीरता से लिया है और अभी जैसा कि समाचार पत्रों में भी इस बात का उल्लेख किया गया है कि उन्होंने कुछ केन्द्रीय मंत्रियों की इस संबंध में एक समिति भी बना दी है जो यह सुनिश्चित करेगी कि जैन कमीशन को पर्याप्त सहयोग दिया जाए। इस संबंध में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का जो अधिवेशन हुआ था, उसमें भी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने एक प्रस्ताव पारित करके यह सुनिश्चित किया था कि जैन कमीशन को पर्याप्त सहयोग दिया जाना चाहिए और जो वांछित दस्तावेज हैं, वह उसको उपलब्ध कराए जाने चाहिए।

मान्यवर, 31.7.1992 को जैन कमीशन की सिटिंग प्रारंभ हुई है लेकिन उसके बाद से अभी 9 अगस्त को जो आखिरी सिटिंग हुई, उसके बाद और आगे होनी है, वह कमीशन ठीक ढंग से काम कर पाए, उसके लिए उसे जो सहयोग दिया जाना चाहिए, वह नहीं मिल पाया है। एक और गंभीर बात, जिसकी वजह से मैं आज सदन में खड़े होकर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, वह यह है कि अभी समाचार पत्र में यह छपा है, वह समाचार पत्र मेरे पास है, कि गृह मंत्रालय की तरफ से उसके वकील ने एक प्रेसी जैन कमीशन के सामने प्रस्तुत की है जिसमें जैन कमीशन को वाइंड-अप करने का प्रस्ताव दिया गया है। यह बहुत अफसोसजनक और दुख भरी बात है। मान्यवर, इस सदन में, चाहे किसी भी पक्ष के माननीय सदस्य क्यों न हों, सब सदस्यों ने राजनीतिक पार्टियों से परे रहकर यह मांग की थी कि हमारे नेता श्री राजीव गांधी जी की जो निर्मम हत्या हुई है, उसकी जांच की जानी चाहिए और उस साजिश में जो-जो संबद्ध रहे हों, उनका व्यापक रूप से पता लगाने के लिए कमीशन की स्थापना की जानी चाहिए और उस कमीशन को पर्याप्त सहयोग प्रदान किया जाना चाहिए। लेकिन जैन कमीशन की स्थापना के बाद लगातार जो सिटिंग्स हो रही हैं, उनमें उन्हें पर्याप्त दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए जा रहे हैं और उसको जो सहयोग दिया जाना चाहिए, वह नहीं दिया जा रहा है, ऐसा समाचार-पत्रों के माध्यम से हम लोगों को आभास हो रहा है।

समाचार-पत्रों में यह भी आया है कि हमारे प्रधान मंत्री जी ने इस को गंभीरता से लेकर एक समिति का गठन किया है। वह समिति यह सुनिश्चित करेगी कि जैन कमीशन को पर्याप्त सहयोग दिया जाए तो मैं आप के माध्यम से सरकार से यह जानना चाहता हूं कि समाचार-पत्रों में जो सब चीजें प्रकाशित हुई हैं वह यदि सही हैं तो यह अत्यंत गंभीर और खेदजनक बात है। सरकार को यह निर्देश दिया जाना चाहिए कि श्री राजीव गांधी जी कि साज़िश के संबंध में जो जैन कमीशन की स्थापना की गई है उसको पर्याप्त सहयोग दिया जाए।

मान्यवर, इस संबंध में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा एक पत्र लिखा गया है, मेरे पास उस पत्र की प्रतिलिपि है, श्री अहमद पटेल ने 28 सितंबर 1993 को पत्र लिखा था जो जैन कमीशन को लिखा था और जैन कमीशन से उन्होंने यह आग्रह किया था कि सरकार को जो कुछ डाक्यूमेंट्स जैन कमीशन को चाहिए वह उसके समक्ष प्रस्तुत करे। मैंने यह सवाल पिछली बार भी किया था और सरकार ने यह आश्वासन भी दिया था लेकिन उस आश्वासन की पूर्ति अभी तक नहीं हो पाई है। उस आश्वासन की पूर्ति तो नहीं हुई आज ये चौंकाने वाला समाचार हमारे समाचारपत्रों में छपा है। इससे निश्चित रूप से हमें बहुत दुख हो रहा है। इसलिए आप का संरक्षण चाहते हुए मैं केन्द्रीय सरकार से यह आग्रह करूंगा कि जैन कमीशन को पूरा सहयोग दिया जाए और जो भी दस्तावेज उन्होंने मांगे हैं वह उनको उपलब्ध कराए जाएं ताकि जैन कमीशन अपने काम को पूरा कर सके।

श्री रजनी रंजन साहू (बिहार): महोदय, मैं अपने आप को श्री सुरेश पचौरी जी के साथ संबद्ध करता हूं। इन की जो ऐक्जाइटी है वह सभी सदस्यों की ऐक्जाइटी है कि जैन कमीशन को प्रापर कागज़ात उपलब्ध कराए जाएं। यह मेरी भी मांग है।

कुमारी सरोज खापर्डे (महाराष्ट्र): उपसभाध्यक्ष महोदय, श्री सुरेश पचौरी जी ने अपने सेंटीमेंट्स सदन के सामने व्यक्त किए हैं उनमें वास्तविकता है और उन्होंने जिस अखबार का हवाला दिया है उस अखबार को देखने के बाद ऐसा लगता है कि राजीव गांधी जी की निर्मम हत्या को सही ढंग से हम लोग नहीं ले रहे हैं और जो हम ने सेक्शन किया है, जैन कमीशन की नियुक्ति की है उस को जिन-जिन दस्तावेजों की जरूरत है, जिनकी उन्होंने मांग की है उन को उन दस्तावेजों की फाइल न तो केन्द्रीय सरकार की ओर से पेश की जा रही है, न तमिलनाडु सरकार की ओर से पेश की जा रही है। इसी कारण राजीव गांधी जी की हत्या के बारे में सही पर्दाफश होकर लोगों के सामने आएगा ऐसा प्रतीत नहीं होता। मैं माननीय सुरेश पचौरी जी के वक्तव्य से सहमत हूं और सरकार से अनुरोध

करूंगी कि जिन-जिन दस्तावेजों की, जिन जिन कागज़ात की जैन कमीशन ने मांग की है उन कागज़ातों को अपनी ओर से और तमिलानाडु सरकार की ओर से जैन कमीशन के सामने भेजें ताकि देश की जनता को और इंटरनेशनल वर्ल्ड को भी उनकी हत्या के बारे में सही पता चल सके। धन्यवाद।

श्री सैयद सिब्ते रज़ी (उत्तर प्रदेश) मान्यवर, राजीव गांधी की हत्या किसी साधारण व्यक्ति की हत्या नहीं थी। वह देश के प्रधान मंत्री थे और इस देश के करोड़ों करोड़ इंसानों के दिलों में रचे बसे व्यक्ति थे। उनकी हत्या से सारे देश के अंदर ही नहीं, सारी दुनिया के अंदर एक ग़म और अफ़सोस की लहर दौड़ गई थी। जिस प्रकार से विश्व के दर्जनों राजनेता, प्रधान मंत्री और लीडर उनके लास्ट राइट्स में शिरकत करने के लिए आए थे उस से पता चलता है कि थोड़े से ही अरसे में उन्होंने केवल भारत में ही नहीं बल्कि सारी दुनिया के अंदर अपनी एक जगह बना ली थी। दुनिया के जो लोग नस्ल और रंग के शिकार हुए थे उन के अंदर भी वह एक आशा की किरण थे। आज इस प्रकार की जो न्यूज छपी है वह बड़ी डिस्टर्बिंग न्यूज है और अगर उस न्यूज में कोई तत्व है तो सरकार उस पर ध्यान देगी। मैं समझता हूं कि हमारी पार्टी की सरकार आज देश में बनी हुई है, हमारी सरकार इस बात को पसंद नहीं करेगी कि राजीव गांधी जैसे महान व्यक्ति की हत्या के संबंध में किसी भी तरह की लिथार्जी या सुस्ती पैदा हो जाए। मुझे आशा है कि केन्द्रीय सरकार पचौरी जी द्वारा उठाए गए मामले पर गौर करेगी। जो भी दस्तावेज या जो भी सूचनाएं, जो भी इन्फरमेंशन इस कमीशन को जरूरत है राज्य स्तर पर तो वह अपने प्रभाव का प्रयोग करेगी और केन्द्रीय सरकार भी अपने दायित्व का निर्वहन करेगी। मुझे आशा है केन्द्रीय सरकार इसमें पूर्णरूप से दिलचस्पी ले रही लेकिन यदि किसी स्तर पर उसमें कोई कमी पाई जा रही है तो उसको दूर करके उसमें और ज्यादा तेजी लायेगी और जल्दी से जल्दी इस चीज का निपटारा हो जायेगी। उसमें यह पता लग जायेगा कि राजीव गांधी की हत्या के पीछे कौन सी बड़ी साजिश थी और कौन इसमें पूर्ण रूप से स्वादवा है।

شری سید سبط رضی "اتر پردیش": مانیہ ور راجیو گاندھی کی ہتیا کسی سادھارن وکتی کی ہتیا نہیں تھی وہ دیش کے پردھان منتری تھے اور اس دیش کے کروڑوں انسانوں کے دلوں میں رچے بسے وکتی تھے انکی ہتیا سے سارے دیش کے اندر ہی نہیں ساری دُنیا کے اندر ایک غم اور افسوس کی لہر دوڑ گئی تھی جس پرکار سے وشو کے درجنوں راج نیتا پردھان منتری اور لیڈر انکے لاسٹ رائیٹس میں شرکت کرنے کے لئے آئے تھے اس سے پتہ چلتا ہے کہ تھوڑے سے ہی عرصہ میں انہوں نے کیول بھارت میں ہی نہیں بلکہ ساری دنیا کے اندر اپنی ایک جگہ بنالی تھی۔ دُنیا کے جو لوگ نسل اور رنگ کے شکار ہوئے تھے۔ ان کے اندر بھی وہ آشا کی ایک کرن تھے۔

آج اس پرکار کی جو نیوز چھپی ہے وہ بڑی ڈسٹربنگ نیوز ہے اور اگر اس نیوز میں کوئی تتو ہے تو سرکار اس پر دھیان دیگی میں سمجھتا ہوں کہ ہماری پارٹی کی سرکار آج دیش میں بنی ہوئی ہے۔ ہماری سرکار اس بات کو پسند نہیں کرے گی کہ راجیو گاندھی جیسے مہان وکتی کی ہتیا کے سمبندھ میں کسی بھی طرح کی لاپرواہی یا سستی پیدا ہو جائے۔ مجھے آشا ہے کہ کیندریہ سرکار پچوری جی دوارا اُٹھائے گئے معاملہ پر غور کرے گی۔ جو بھی دستاویز یا جو بھی سوچنا جو بھی انفارمیشن اس کمیشن کو ضرورت ہے راجیو سرکار کے استر پر تو وہ اپنے پربھاؤ

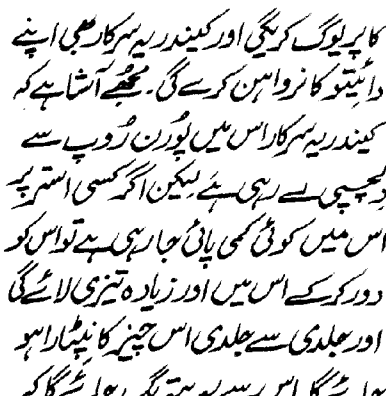

"ختم شد"

श्री गोविन्दराव आदिक (महाराष्ट्र): माननीय सुरेश पचौरी जी ने जो यहां मुद्दा उठाया है उसके प्रति अपनी सहमति व्यक्त करने के लिए मैं आपके समाने खड़ा हुआ हूं। जो बातें यहां कही गई उसको मैं दोहरांना नहीं चाहता इसलिए कि उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। जरूर यहां कहना होगा कि जो समाचार हमारे सामने सदन के सामने रखा गया इस समाचार को बड़ी गम्भीरता से देखने वाली बात बन गई है। यहां जिक्र किया गया जैन आयोग का जिसका हमने निर्माण किया था कि वह स्वर्गीय राजीव गांधी की हत्या के बारे में पूरी जांच करे और उसमें केन्द्रीय सरकार और बाकी एजेंसीज उन्हें पूरा सहयोग दे। मामला इसी बात तक समाप्त नहीं होता ऐसा मैं मानता हूं। जो समाचार छप गया है उसमें यह भी लिखा गया है जैन आयोग को समाप्त करने के लिए भारत के गृह मंत्रालय की ओर से एक निवेदन केन्द्रीय मंत्रिमंडल के सामने लाया गया था। यह सुनने के बाद और यह समाचार पढ़ने के बाद लोगों के दिल में आंशकाएं पैदा होती हैं कि केन्द्रीय शासन सही माने में राजीव गांधी की हत्या के बारे में जांच करना चाहता है या नहीं। अगर केन्द्रीय सरकार राजीव गांधी की हत्या के बारे में जांच करना अपना कर्तव्य मानती है तो केन्द्रीय शासन के होम डिपार्टमेंट की तरफ से यह टिप्पणी केन्द्रीय मंत्रिमंडल के सामने कैसे आ सकती है? यह सवाल हमारे सब के सामने खड़ा हुआ है। इसलिए यह उचित होगा कि केन्द्रीय सरकार सामने आकर इस बारे में जो वास्तविकता है उस बारे में निवेदन करे और जो गलतफहमियां समाज में फैलने की संभावना है उसको रोकने की कोशिश करे।

उपसभाध्यक्ष (श्री वी.नारायणसामी): श्री मूलचन्द मीणा।

SHRI S.S. AHLUWALIA (Bihar): Mr. Vice-Chairman, I had raised my hand first.

THE VICE CHAIRMAN (SHRI V. NARANYANSAMY): Mr. Ahluwalia, before you raised your hand, other Members raised their hands. I have noted it down here. I will call your name later.

SHRI S.S. AHLUWALIA: What is this? I have raised my hand first.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANSAMY): No, no.

श्री मूलचन्द मीणा (राजस्थान): उपसभाध्यक्ष महोदय, सुरेश पचौरी जी ने जो अपनी भावनाएं व्यक्त की है उनसे अपनी सहमति व्यक्त करते हुए कहना चाहता हू कि राजीव गांधी कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। एक असाधारण व्यक्ति की जो हत्या हुई है हमारी सरकार ने उस हत्या में शामिल लोगों का पता लगाने के लिए जैन आयोग की स्थापना की थी। लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि गृह मंत्री जी का जवाब सुरेश पचौरी जी को मिला और जैन आयोग की जो रिपोर्ट अखबारों में देखने को मिली इसमें अंतर क्यों है। गृह मंत्री जी एक तरह कहते हैं कि हम सारी जांच से सम्बन्धित कागजात उपलब्ध करायेंगे और जैन आयोग कहता है कि हमें जांच से सम्बन्धित सारे कागजात उपलब्ध नहीं कराये गये। इससे शंकाएं पैदा होती हैं । इससे सरकार के ऊपर भी शंकायें पैदा की जा सकती हैं कि क्या सरकार की जो मंशा राजीव गांधी के हत्यारों का पता लगाने की है, उससे कहीं विचलित तो नहीं हो रही है। इसलिए मैं यह चाहता हूं कि राजीव गाधी की हत्या जिस तरह की की गयी, जिस घिनौने तरीके से की गयी और इसके पीछे जिन भी लोगों का हाथ है, जो इसमें शामिल हैं, चाहे वे बड़े राजनेता हों या बड़े अधिकारी हों, उनको दंडित किया जाए। इसलिए मैं गृह मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि जिन कागजातों को जैन आयोग ने मांगा है उनको आयोग को तुरन्त उपलब्ध करायें और दोषियों के खिलाफ शीघ्र कड़ी कार्यवाही की जाये। महोदय, भारत की न्याय प्रणाली के अंदर देश की महान नेता श्रीमती इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के हत्यारों को अभी तक

सजा नहीं मिली है। इंदिरा गांधी के हत्यारों को चार साल में जाकर सजा मिली। जो देश के महान नेता थे, जिन्होंने इस देश के लिये अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया, उन नेताओं की हत्या की जांच शीघ्र हो और उसका न्याय शीघ्र होना चाहिए, यह सरकार का काम होना चाहिए। इसके लिये मैं निवेदन करूंगा कि जैन आयोग ने गृह मंत्रालय से जो कागजात मांगे हैं, मंत्रालय उन्हें सारे कागजात जल्दी उपलब्ध कराये। यदि सरकार ऐसा करती है तो निश्चित है कि राजीव गांधी की हत्या में शामिल लोगों का पर्दाफाश होगा और उनको दंड मिलेगा।

श्री एस॰एस॰ अहलुवालिया: उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं अपने मित्र श्री सुरेश पचौरी जी द्वारा उठाये गये इस मुद्दे का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं और अपने आपको इससे सबद्ध करता हूं।

महोदय, इस सदन में जैन कमीशन की मांग और वर्मा कमीशन की मांग करने वाले उन तमाम सदस्यों में से मैं भी एक सदस्य था जिसने यह मांग की थी। जैन कमीशन की बात हम तब करें जब वर्मा कमीशन के जो नतीजे हैं उनमें कहीं भी कोई कार्यवाही की गई हो। अभी तक वर्मा कमीशन के जो नतीजे आये हैं उन पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है। वर्मा कमीशन ने कहा था कि राजीव गांधी जी की सुरक्षा व्यवस्था बिना किसी अल्ट्रानेटिव सुरक्षा के बंदोबस्त के कारण, उनकी हत्या हुई। उसके आधार पर उस टाइम के प्रधानमंत्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह पर सीधा क्रिमिनल केस होना चाहिए था, जो आज तक नहीं हुआ। वर्मा कमीशन ने जिन-जिन मुद्दों को लेकर सामने खड़ा हुआ था आज तक उन पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। महोदय, आज के दिन हमारे सामने बहुत सारे सवाल उभरकर सामने आते हैं। सुरेश पचौरी जी ने जिस बात का उल्लेख किया है कि किसी का नोटिस गया है, तो एक वकील ने केस किया है और कहा है कि वर्मा कमीशन के टर्म्स आफ रेफरेंस और जैन कमीशन के टर्म्स आफ रेफरेंस में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है और जैन कमीशन के टर्म्स आफ रेफरेंस पूरी तरह से स्पेसिफाई नहीं हैं। इस तरह से उसने केस फाइल किया है कि उसने कहा है कि इसके तहत जैन कमीशन को वाइंड-अप किया जाए। मैं इस चीज से घबरा नहीं रहा हूं कि जैन कमीशन वाइंड-अप हो जायेगा क्योंकि मुझे विश्वास है कि यह केस सुप्रीम कोर्ट से खारिज होगा। खारिज होना पड़ेगा। उपसभाध्यक्ष महोदय, मेरा कहना सिर्फ यही है कि जब कमीशन बनाया जाता है जो उसके जो निर्णय हों, उन निर्णयों को लागू किया जाए। अभी तक विश्वनाथ प्रताप सिंह के खिलाफ क्रिमिनल केस फाइल नहीं हुआ। मैं उनके खिलाफ क्रिमीनल केस फाइल करने के मांग करता हूं।

दूसरी मांग में यह करता हूं कि अभी हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति ने जो कुछ कहा है आज तक तो चुप थे भारत के लोग, पूरे भारत के लोग जिनको राजीव गांधी के व्यक्तित्व से प्रेम था, राजीव गांधी से प्रेम था, वे चुप थे। भूतपूर्व राष्ट्रपति श्री वेंकटरमण जी ने जो उनके बारे में कहा है, उसके बाद हमारी मांग है और सारे भारत के लोगों की मांग है कि उन्हें जैन कमीशन के सामने पेश किया जाए क्योंकि राजीव गांधी की जिस वक्त हत्या हुई इसमें वह दो तरह से जिम्मेदार हैं। एक तरह से जिम्मेदार हैं कि जिस वक्त उनकी एस.पी.जी. विदड्रा की गई थी, उस वक्त कांग्रेस के समस्त लोक सभा और राज्य सभा के सदस्य जा कर राष्ट्रपति से मिले थे। उन्होंने राष्ट्रपति जी को कहा था कि राजीव गांधी की एस.पी.जी. सिक्युरिटी विदड्रा कर ली है, इसलिए उनकी सुरक्षा की व्यवस्था की जाए, आप इस पर इंटरवीन करें लकिन वह मूकदर्शक बन कर बैठे रहे और उन्होंने कभी इंटरवीन नहीं किया। वह तमिलनाडु के रहने वाले थे इसलिए भी उनको एल.टी.टी.ई. की थ्रेट का मालूम था। वह राष्ट्रपति थे, सर्वोपरि थे भारत की हर चीज़ की इनफॉरमेशन उनके पास थी। इसके बावजूद उन्होंने इंटरवीन नहीं किया। इंटरवीन करते तो शायद विश्वनाथ प्रताप सिंह इतनी हिम्मत नहीं कर सकते थे कि एस.पी.जी. विदड्रा हो जाती। आज पी.वी. नरसिंह राव जी सोनिया गांधी तथा भूतपर्व प्रधान मंत्रियों को एस.पी.जी. सुरक्षा व्यवस्था में लाने के लिए एक्ट को अमेड करने का उपराला कर सकते हैं और अमेड कर सकते हैं, वही बात विश्वनाथ प्रताप सिंह भी राष्ट्रपति के कहने पर कर सकते थे पर राष्ट्रपति ने ऐसा नहीं किया और उसी भूतपूर्व राष्ट्रपति के राष्ट्रपतिकालीन राष्ट्रपति शासन के बीच ही राजीव गांधी की हत्या तमिलनाडु में हुई, उस भूतपूर्व राष्ट्रपति के खिलाफ भी क्रिमिनल केस फाइल होना चाहिये और उस भूतपूर्व राष्ट्रपति को भी जैन कमिशन के सामने पेश कर के उससे मांग करनी चाहिये कि क्यों नहीं आपने इसमें इंटरवीन किया जिस वक्त एस.पी.जी. विदड्रा की बात आई थी। कांग्रेस के संसद् सदस्य आपसे मिले थे, उन्होंने जो ज्ञापन दिया था उसको मद्दे नज़र रखते हुए आपने इस पर विचार किया था या नहीं किया था। उनके थ्रेट परसेप्शन की एनेलेसिज़ मांगी थी या नहीं मांगी थी क्योंकि आपके तहत रा डिमार्टमेंट है, आपके तहत इंटेलीजेंस डिमार्टमेंट है, आपके तहत सी.बी.आई. है, इतने डिमार्टमेंट आपको रिपोर्ट करते हैं और उस रिपोर्ट के माध्यम से आपको पता था कि राजीव गांधी को भारतवर्ष में सब से ज्यादा थ्रेट है। सारे विश्व में जितने भी राष्ट्राध्यक्ष हैं या प्रधानमंत्री होते हैं या भूतपूर्व प्रधानमंत्री होते हैं अगर उनका असेस्मेंट किया जाए तो सब से ज्यादा थ्रेट राजीव गांधी को था। उसके

बावजूद भी उनकी सुरक्षा की व्यवस्था नहीं की गई। उसमें जितना दोषी विश्वनाथ प्रताप सिंह को मैं समझता हूं उतना ही दोषी मैं आर. वेंकटरामन को समझता हूं। मैं यह मांग करता हूं कि वो कार्यवाही उनके खिलाफ भी होनी चाहिए और उनको भी जैन कमीशन के समाने बुलाना चाहिये। धन्यवाद।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): Mr. Parliamentary Affairs Minister, may I have your attention? The hon. Members have expressed their concern and the House is unanimous on the Jain Commission's observations in regard to the non-sharing of documents by the Government of India as also by the State Government of Tamil Nadu.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI RAMESHWAR THAKUR): Sir, this is a very serious matter and the concern expressed by the hon. Members will be conveyed to the Home Minister for necessary action.

Proposed Hoisting of National Flag by BJP at Idgah Maidan Hubli

श्री अजीत जोगी (मध्य प्रदेश): उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं अत्यन्त गम्भीर और सार्वजनिक महत्व के विषय की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हम सब को याद है कि किस तरह से इस देश में साम्प्रदायिक और फासीवादी ताकतों ने धर्म के नाम पर लोगों को लड़ा कर आयोध्या को प्रतीक बना कर एक दूसरे से अलग किया था और पूरे देश में साम्प्रदायिक उन्माद व्याप्त हो गया था। मैं बड़े खेद और चिन्ता के साथ यह कहना चाहता हूं कि अब वैसी ही कोशिश जो उत्तर भारत में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, राष्ट्र स्वयं सेवक संघ के लोगों ने, विश्व हिन्दू परिषद के लोगों ने इन फासीवादी ताकतों ने उत्तर भारत में जो कोशिश की थी जिस तरह से उन्होंने पूरे देश को साम्प्रदायिक ज्वाला में झौंक दिया था, बिल्कुल वैसी कोशिश अब दक्षिण भारत में हो रही है। कर्नाटक राज्य के हुबली में ईदगाह मैदान को ले कर उसी तरह से भावनाएं भड़काई जा रही हैं। हुबली का यह ईदगाह मैदान वहां की अंजुमन को सन् 1922 में दिया गया था। उसके बाद से मुसलसल, लगातार अंजुमन के पास ही है। अब कर्नाटक की भारतीय जनता पार्टी ने यह धमकी दी है कि इस 15 अगस्त को हम उस ईदगाह मैदान में सार्वजनिक रूप से तिरंगा झंडा फहरायेंगे। ईदगाह मैदान में झंडा फहराने की जो धमकी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने दी है, उसका लक्ष्य केवल यह है जिस तरह से अयोध्या उन्होंने बाबरी मस्जिद को ले कर, प्रतीक मान कर, उन्माद फैलाया था, उसी तरह से कर्नाटक में हुबली में इस तरह की वारदात कर के, घटना कर के सार्वजनिक आयोजन कर के सार्वजनिक उन्माद फैलाना चाहते हैं। मेरा आपसे इसलिए यह निवेदन है कि इन ताकतों को हमने पहले भुगता है, इन ताकतों के कारण जिस तरह से पूरे देश में धर्म के नाम पर लोग अलग हुए हैं, जिस तरह से धर्म के नाम को इस्तेमाल करके लोगों की भावनाओं को भड़काया गया है जिस तरह से देश की प्रगति को, उन्नति को रोका गया है, इसलिए इन ताकतों की साजिश पर, इनके षडयंत्र पर रोक लगाना बहुत जरूरी है। 15 अगस्त को जो भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक में करना चाहती है, उसमें वह केवल राजनैतिक लाभ लेना चाहती है और केवल राजनैतिक लाभ के लिए आने वाले विधान सभा चुनाव को देखते हुए वह धार्मिक उन्माद फैलाना चाहती है। ये इनका राजनैतिक लाभ लें या न लें पर इससे पूरा देश एक बार फिर से साम्प्रदायिक तनाव में आ जाएगा, फिर से साम्प्रदायिक दंगे होंगे, फिर से भाई भाई से लड़ेगा, फिर से खून की नदियां बहेंगी। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि इस मसले को, इस प्रकरण को केवल कर्नाटक की सरकार पर न छोड़ा जाए। कर्नाटक की सरकार कांग्रेस की सरकार है वह इस तरफ ध्यान दे रही है, पूरा इंतजाम, पूरा बंदोबस्त उन्होंने किया है पर हमें केवल राज्य सरकार पर यह बात नहीं छोड़नी चाहिए, यह एक ऐसी घटना है, एक ऐसा प्रकरण है जिसका पूरे देश से पूरे देश की भावना से, संवेदना से संबंध है। इसलिए केन्द्र सरकार को भी, गृह मंत्रालय को भी इस ओर ध्यान देना चाहिए और जितनी भी इमदाद, जितनी भी मदद कर्नाटक की सरकार को आवश्यक हो वह देनी चाहिए और किसी भी हालत में भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जो आज प्रजातंत्र पर विश्वास नहीं करते, इसलिए संसद में जिनकी ये बेंचे खाली हैं, जिन लोगों के हमारे सर्वोच्च न्यायालय के सामने गलत शपथ पत्र दिया, जिन लोगों ने इस सदन में गलत आश्वासन दिया, जिन लोगों को सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार साम्प्रदायिक करार दिया गया, उनको हम एक मौका फिर से न दें और हुबली में जो ईदगाह मैदान में तिरंगा झंडा फहराने के नाम पर फिर से साम्प्रदायिक तनाव फैलाना चाहते हैं चाहे हमें कितना भी कड़ा प्रयास क्यों न करना पड़े, चाहे कितनी ही पुलिस और पैरा मिलिटरी फोर्स, सेना क्यों न भेजनी पड़े, भारतीय जनता पार्टी के इन प्रयासों को हमें हर हालत में विफल करना चाहिए। उनको इस तरीके से साम्प्रदायिक तनाव फैलाने की कोई इजाजत नहीं देनी चाहिए।